पूर्ण रोजगार के लिए नीति अथवा बेरोजगारी को कम करने के उपाय
(Policy of Full Employment or Measures to reduce Unemployment)

किसी समाज के लिए बेरोजगारी एक अभिशाप है जिसका निराकरण करना आवश्यक है। बेरोजगारी को कम करने एवं पूर्ण रोजगार की स्थिति लाने के लिए मुख्यतः निम्न लिखित नीतियों का सहारा लिया जाता है:-

(1) मौद्रिक नीति (Monetary Policy):- हम देख चुके हैं कि रोजगार प्रभावपूर्ण माँग पर निर्भर करता है जिसके दो अंग हैं - उपभोग सम्बन्धी वस्तुओं की माँग तथा विनियोग सम्बन्धी वस्तुओं की माँग। अतः रोजगार एवं उत्पादन में वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक है कि उपभोग एवं विनियोग पर किये गये व्यय में वृद्धि की जाय। इस संबंध में मौद्रिक नीति (Monetary policy) का विशेष महत्व है। लेकिन चूँकि उपभोग की प्रक्रिया (consumption function) अल्पकाल में प्रायः स्थायी रहती है अतः मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य विनियोग (investment) में वृद्धि करना होना चाहिए। मौद्रिक नीति से हमारा तात्पर्य सरकार एवं केन्द्रीय बैंक की उस नीति से है जिसके माध्यम से चलन एवं साख (Currency and credit) में परिवर्तन लाकर वांछित उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। बेरोजगारी एवं मंदी की अवस्था में निजी विनियोग (Private Investment) में कमी आ जाती है। अतः बेरोजगारी को कम करने के लिए मौद्रिक नीति द्वारा निजी विनियोग में वृद्धि करना आवश्यक है।

(2) राजकोषीय नीति (Fiscal Policy):- पूर्ण रोजगार की प्राप्ति में राजकोषीय नीति अत्यन्त सहायक सिद्ध होती है। राजकोषीय नीति द्वारा पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए (1) बजट नीति (2) सार्वजनिक व्यय की नीति (3) करारोपण नीति एवं सार्वजनिक ऋण की नीति का सहारा लिया जाता है। इन नीतियों द्वारा प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि करने की चेष्टा की जाती है।

(3) उद्योगों के स्थानीयकरण को नियंत्रित करना (controlling the location of industries):- रोजगार में वृद्धि करने के लिए उद्योगों के स्थानीयकरण को नियंत्रित करना भी आवश्यक है। समाज में उचित व्यय (adequate outlay) होते हुए भी बेरोजगारी की समस्या हो सकती है यदि उद्योगों का समुचित स्थानीयकरण नहीं हो। उदाहरण के लिए, एक स्थान पर मजदूर बेरोजगार रह सकते हैं जबकि दूसरे स्थान पर रोजगार के लिए

Scanned with CamScanner

जगह खाली हो। इसलिए बेरोजगारी को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योगों का समुचित स्थानीयकरण किया जाय और उनका एक ही स्थान पर अत्यधिक केन्द्रीयकरण न हो। इसके लिए देश के विभिन्न भागों में कुल व्यय का उचित वितरण होना चाहिए तथा योजना में आंचलिक दृष्टिकोण (Regional approach in planning) अपनाना चाहिए।

(4) मूल्य समर्थन नीति (Price-Support Policy):- मंदी एवं बेरोजगारी को रोकने के लिए मूल्य समर्थन नीति की सिफारिश की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मंदी के समय जब वस्तुओं के मूल्य गिर रहे हों तो सरकार को अत्यधिक मात्रा में वस्तुओं को खरीदकर उनका संचय (store) करना चाहिए ताकि मूल्यों को गिरने से रोका जा सके। इससे मंदी की अवस्था में व्यवसायियों में आशा का संचार होता है और वे विनियोग कार्यों को हाथ में लेते हैं। इस प्रकार मूल्य-समर्थन नीति का मंदी के विरुद्ध प्रयोग कर रोजगार में वृद्धि की जा सकती है।

(5) श्रम की सुव्यवस्थित गतिशीलता (Organised mobility of labour):- कभी-कभी श्रम-बाजार की अपूर्णताओं (Imperfections of labour market) एवं श्रम की गतिशीलता में बाधा उत्पन्न होने से भी बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अतः रोजगार में वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक है कि श्रम की गतिशीलता को सुव्यवस्थित किया जाय। इसके लिए Employment Exchanges का सहारा लिया जा सकता है जो श्रम की पूर्ति के प्रवाह को श्रम की माँग के अनुसार सुव्यवस्थित कर सके। श्रम की गतिशीलता में वृद्धि करने के लिए श्रम-बाजार को सुव्यवस्थित करना ही जरूरी नहीं है वरन् गतिशीलता के मार्ग में आनेवाली बाधाओं (obstacles) को दूर करना भी आवश्यक है। इसके लिए विभिन्न व्यवसायों एवं पेशों में प्रवेश पर लगाये जानेवाले रोकों को दूर करना जरूरी है।

(6) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (International co-operation):- अन्त में प्रो० कुरिहारा (Prof. K.K. Kurihara) ने अपनी पुस्तक "Monetary Theory and Public Policy" में यह बतलाया है कि पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राप्त करना आजकल नितान्त आवश्यक है। यह सहयोग विकसित एवं औद्योगिक देश मौद्रिक, व्यावसायिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में प्रदान कर सकते हैं। इस संबंध में

अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने सराहनीय कार्य किया है। अतः एक विस्तृत एवं केन्द्रीयकृत नियंत्रण एवं योजना (comprehensive and centralized control and planning) के अभाव में पूर्ण रोजगार की नीतियाँ असफल सिद्ध हो सकती हैं। इस प्रकार नियंत्रण एवं योजना पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रायः देखने को नहीं मिलती। इस प्रकार का नियंत्रण एवं योजना तो समाजवादी अर्थव्यवस्था (Socialist Economy) में ही संभव है। इसलिए प्रो० पीगू (Prof A.C Pigou) ने ठीक ही कहा है — "बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए केन्द्रीय योजना से युक्त समाजवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में निश्चित ही अधिक लाभ प्राप्त होता है।"

(For tackling the problem of unemployment, a socialist system with central planning has a definite advantage over a capitalist one)

Scanned with CamScanner